फरवरी 2023

₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

जातीय जनगणना

समाजवादी जगाएंगे अलख

R.N.I. No. 68832/97

जाति आधारित जनगणना उन पिछड़ी और दलित जातियों के लिए सम्मान का जरिया बनेगी जिन्हें आजादी के बाद आज तक उपेक्षित किया गया है। जातिगत जनगणना से इन जातियों को अपना हक मिलेगा और उनकी पहचान भी बनेगी।

मुलायम सिंह यादव

संस्थापक , समाजवादी पार्टी

समाजवादी बुलेटिन

फरवरी 2023

वर्ष 24| संख्या 04

प्रिय पाठकों

आप सभी के प्यार, उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन से आपकी प्रिय पत्रिका समाजवादी बुलेटिन, बदली हुई साज-सज्जा के साथ अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। हम आपके आभारी हैं कि अभी तक के सफर में हम आपकी कसौटी पर खरे उतर सके हैं। हम भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृपया अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।

धन्यवाद

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

samajwadibulletin19@gmail.com

bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित

अवध पब्लिशिंग हाउस, 8 पान दरीबा, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

अंदर

सदन में गरजे समाजवादी 06

22 कवर स्टोरी

समाजवादी जगाएंगे अलख

निकल पड़े अखिलेश, समर अभी है शेष 12

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2023 की शुरुआत के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का दौरा तेज कर दिया है। हाल ही में करीब आधा दर्जन जनपदों के उनके दौरे में उनकी एक झलक पाने की लोगों की ललक देखते ही बनी।

लोकतंत्र की कमजोर कड़ियां 04

आम बजट : गरीब-ग्रामीण पर चोट 40

लोकतंत्र की कमजोर कड़ियां

उदय प्रताप सिंह

किसी इमारत की अगर एक ईंट कमजोर हो जाए तो समझदार मकान मालिक उसकी तुरंत मरम्मत करते हैं अन्यथा दीवार कमजोर हो गईं तो इमारत भी कमजोर होगी। उसी तरह से किसी देश के लोकतंत्र में यदि कहीं थोड़ी सी भी अलोकतांत्रिक गतिविधि या क्रिया नजर आती हो तो उसको तुरंत ध्यान देकर संभालना चाहिए अन्यथा लोकतंत्र को तानाशाही में बदलते देर नहीं लगती, दुनिया के कई देशों में इसका अनुभव इतिहास में मिलता है।

भारत में अभी हाल ही में बीबीसी के ऊपर आईटी का छापा सिर्फ इसलिए पड़ा या डाला गया कि बीबीसी के एक कार्यक्रम में गुजरात के 2002 के दंगों के हवाले से टीवी पर एक कार्यक्रम दिखाया था, जो भारत में अल्पसंख्यकों पर हुए चर्चित अत्याचारों की एक झलक थी। स्पष्ट है कि भारत सरकार इसी बात पर नाराज होकर आईटी के छापों द्वारा बीबीसी को धमकाने का काम कर रही

है। इंडियन एक्सप्रेस के कार्टून में भी यही सत्य प्रदर्शित किया गया है। हालांकि बीबीसी बहुत पहले से भारत की खबरों के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय एजेंसी मानी जाती रही थी। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दुखद हत्या की ख़बर उनके पुत्र राजीव गांधी ने बीबीसी से सुनकर ही सच मानी थी।

भारत की समाचार एजेंसियां भी उनकी सरकार में यह समाचार दे रही थी पर उनकी विश्वसनीयता, राजीव गांधी की नजर में बीबीसी की तुलना में कम थी। अब प्रश्न उठता है कि बीबीसी के चरित्र में बीजेपी की सरकार आते ही यकायक ऐसी क्या कमी आ गई कि उसकी मरम्मत करने की सरकार को जरूरत पड़ गई, उसको सबक सिखाने की आवश्यकता सरकार को पड़ गई? यह कोई अच्छा संकेत नहीं है।

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा खंभा माना जाता था। भारत की मीडिया का इस समय जो हाल है वह किसी से छुपा नहीं है। भारत की मीडिया सरकार से जनता के हक में प्रश्न करने में डरती है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है , उसकी जवाबदेही होती है और उसी जवाबदेही के तहत उससे प्रश्न किए जाते हैं।

संसद और विधानसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यही प्रश्न पूछने का काम करते हैं। सदनों के बाहर पत्र पत्रिकाओं में यह काम मीडिया का है, समाचार एजेंसीज का है जोकि हमारे यहां दुर्भाग्यवश बहुत कमजोर हो चुकी हैं। उधर सरकार का यह रवैया हो गया है कि अगर जनता में से उसकी जनविरोधी नीति का कोई व्यक्तिगत विरोध करता है या उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे तुरंत राष्ट्रद्रोही करार देकर जेल भेज दिया जाता है। कई न्यायालयों के फैसलों में भी कहा गया है कि यह अच्छा संकेत नहीं है। अभी हाल में कानपुर देहात के एक गांव में एक कमजोर वर्ग की मां बेटी की जिस प्रकार दुखदायी तरीके से मृत्यु हुई है, उस पर सरकार किसी विपक्षी दल के नेता को उस परिवार से मिलने नहीं देती।

अलोकतांत्रिक गतिविधियां लोकतंत्र को आहिस्ता आहिस्ता तानाशाही में बदलती हैं और अवाम को क्रांति करने को विवश करती हैं। लोकतंत्र में सरकारों के इस रवैये के खिलाफ जनता को आवाज उठानी चाहिए। जो समझदार लोग हैं उनको इस पर चर्चा करनी चाहिए

समाजवादी पार्टी के दो चुने हुए विधायकों को पुलिस ने उस गांव में जाने से रोक दिया। वे लोग इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए उस गांव में जाना चाहते थे, उस परिवार से बातचीत करना चाहते थे, जनप्रतिनिधि होने के नाते से उन्हें सांत्वना देना चाहते थे। अगर सरकार विपक्ष के चुने हुए नेताओं व प्रतिनिधियों को जनता के पक्ष में आवाज उठाने की अनुमति नहीं देती तो वह सरकार किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी।

देखने में चाहे यह साधारण घटनाएं लगती हों लेकिन बीबीसी पर आईटी का छापा या विपक्ष के नेताओं को जनता के पक्ष में आवाज उठाने के एवज में गिरफ्तार करना, उन्हें रोकना, यह लोकतंत्र के ठीक विपरीत प्रक्रियाएं हैं। यही अलोकतांत्रिक गतिविधियां लोकतंत्र को आहिस्ता आहिस्ता तानाशाही में बदलती हैं और अवाम को क्रांति करने को विवश करती हैं।

लोकतंत्र में सरकारों के इस रवैये के खिलाफ जनता को आवाज उठानी चाहिए। जो समझदार लोग हैं उनको इस पर चर्चा करनी चाहिए और मीडिया न सही लेकिन जो कलम के धनी हैं उन्हें लोकतंत्र की रक्षा हेतु आगे आकर इनपर अपनी कलम चलानी चाहिए।

जयहिंद!

जनहित के मुद्दों पर सदन में गरजे समाजवादी

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के बजट सत्र की 20 फरवरी को हुई शुरुआत के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जनहित के मुद्दों पर सदन के अंदर और सड़क पर भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जातीय जनगणना की मांग समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा।

सदन के अंदर खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों का नेतृत्व किया। श्री अखिलेश यादव अपने हाथ में तख्ती भी लिए थे जिस पर नारा लिखा था,

जातीय जनगणना कराए सरकार
सबको सम्मान, सबको अधिकार॥

समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूरा समय जबरदस्त नारेबाजी कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के

खिलाफसदन में अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी के विधायक अपनी जगह पर खड़े होकर हाथों में नारे लिखी तख्तियां लहराते रहे जिन पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की दुर्दशा, भर्तियों में धांधली, दलितों, पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को प्रमुखता से उठाया गया। हाल ही में कानपुर देहात में योगी सरकार की जानलेवा बुलडोजर नीति के कारण मां और बेटी की जलकर हुई मौत का मामला भी सपा के विधायकों ने जोर-शोर से उठाया। सदन की बैठक शुरू होने से पहले विधान भवन के प्रवेश द्वार पर भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वरिष्ठ विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में जबरदस्त धरना प्रदर्शन एवं नारेबाजी की।

समाजवादी पार्टी के विधायकों के तेवरों से हतोत्साहित सुरक्षाकर्मियों ने कवरेज कर रहे हैं मीडिया कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट तक की। जिसमें कई मीडिया कर्मी घायल हुए। इस घटना ने फिर एक बार साबित कर दिया की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक परंपराओं पर कोई विश्वास नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार लाख जुल्म करे लेकिन सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार की तानाशाही का विरोध जारी रहेगा।

मीडिया कर्मियों पर हमले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने पूरे सिस्टम को तानाशाही में बदल दिया है। जनता के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन, आवाज उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। उसकी कवरेज करना मीडिया और पत्रकारों का दायित्व है। लेकिन मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट और अभद्रता की गई जो लोकतंत्र में निन्दनीय है। मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़े गए तथा उन्हें लातघूंसे मारे गए। क्या यही भाजपा का लोकतंत्र है। भाजपा लोकतंत्र को नहीं मानती है।

इससे पूर्व विधानमंडल बजट सत्र में भाग लेने पहुंचे सपा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोला। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जातीय जनगणना करवाने की समाजवादी पार्टी की मांग को दोहराते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। इसलिए उन्हें जातीय जनगणना की जरूरत से भी कोई वास्ता नहीं है।

जातीय जनगणना कराए सरकार!
सबको सम्मान, सबको अधिकार!
कहाँ हुई एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी,
किस मंडल में नई यूनिवर्सिटी बनी?
भाजपाइयों के वादे सभी अधूरे,
सिर्फ कागज़ पर करते हैं पूरे
जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही सरकार
जवाब दो! जवाब दो!

जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही सरकार
जवाब दो! जवाब दो!

फोटो: सुमित कुमार

फोटो: सुमित कुमार

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में निवेश लाने का ढिंढोरा पीट रही है लेकिन यह सरकार ऐसी है जो सड़क पर लगाए गए गमलों और पौधों को भी बचा नहीं पाई। सब चोरी हो गए। जो सरकार गमले, फूल और पेड़ नहीं बचा पा रही है वह क्या इन्वेस्टमेंट लाएगी। कानपुर देहात में मां बेटी की जान चली गई, उसका कारण प्रशासन सरकार और बुलडोजर है। बुलडोजर वाली सरकार से इन्वेस्टमेंट लाने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

फोटो स्रोत : गूगल

जानलेवा बुलडोजर नीति!

बुलेटिन ब्यूरो

कानपुर देहात जनपद में प्रशासनिक मनमानी के कारण बुलडोजर चलाकर घर गिराने की कार्रवाई के दौरान मां और बेटी के जिंदा जल कर मर जाने की घटना ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि भाजपा राज कितना असंवेदनशील है। भाजपा राज में पूरा पुलिस प्रशासन तंत्र निरंकुश तरीके से काम कर रहा है लेकिन सरकार इससे बेखबर है या फिर उसे खबर भी है तो वह बेफिक्र है। सरकार का पूरा जोर इस पर है कि कहीं समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ित पक्ष से जाकर मिल न लें और कहीं अपने संवेदना प्रकट न कर दें। कानपुर देहात मामले में भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर कानपुर देहात के पीड़ित परिवार से मिलने सपा विधायक दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय के नेतृत्व में जा रहे पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने जाने से रोक दिया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधायकों एवं नेताओं ने सड़क पर धरना शुरू करके पुलिस प्रशासन और सरकार की इस

भाजपा राज में अन्याय चरम पर

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। प्रशासन पूरी तरह बेरहम और अमानवीय हो चला है। सत्ता के अंहकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया।

निर्दोषों की हत्या हो रही है। भाजपा ने बुलडोजर को अपनी गैरकानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मैथा तहसील की मडौली पंचायत के चाहला गांव में एसडीएम, लेखपाल ने गरीब परिवार का घर बुलडोजर से ध्वस्त किया। आग लगने के कारण मां-बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह घटना दिल दहलाने वाली है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर देहात की दर्दनाक घटना में श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी श्रीमती प्रमिला दीक्षित, बेटी नेहा की जलकर मौत हो गई। परिवार के बेटे ने नाम लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी ठहराया है। यह बड़े अफसोस और क्षोभ की बात है कि जलते घर से मां-बेटी की चीखें आ रही थीं मौजूद अफसरान वहां से भाग खड़े हुए। जलती लाशें प्रशासन की निर्लज्जता की कहानी कहती है।

पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोकना सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि सरकार शासन-प्रशासन भय और उत्पीड़न की प्रतीक बन गई। भाजपा सरकार का अंत बहुत ही निकट है।

मनमानी का भरपूर विरोध किया।

कानपुर देहात में घटना स्थल पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोकने के लिए सरकार ने तमाम तरह के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हथकंडे अपनाये। कानपुर जिला प्रशासन ने अपने दुष्कृत्य को छुपाने के लिए सुबह से श्री अमिताभ बाजपेयी विधायक के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया और बाहर निकलने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन ने डॉ मनोज पाण्डेय एवं उदय राज यादव पूर्व विधायक और अन्य नेताओं को कानपुर जाते समय जाजमऊ के पहले ही रोक दिया। जिसके बाद मनोज पाण्डेय के नेतृत्व में पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए।

इसी तरह से प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कालपी के विधायक श्री विनोद चतुर्वेदी और विधायक प्रदीप यादव को भी घटना स्थल पर नहीं जाने दिया। यह सरकार और पुलिस प्रशासन जनता और विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। पुलिस का रवैया शर्मनाक और निंदनीय है।

समाजवादी पार्टी ने मांग कि है कि इस काण्ड के आरोपी डीएम, एसडीएम और लेखपाल पर धारा 302 में मुकदमा दर्ज हो, मृतकों के परिजनों को सरकार पर्याप्त एवं उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। पीड़ित परिजनों की मांगों को राज्य सरकार को तत्काल पूरा करना चाहिए।

निकल पड़े अखिलेश समर अभी है शेष

बुलेटिन ब्यूरो

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। चुनावी समर से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल पड़े हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था के मुद्दों पर आक्रोशित लोगों का सपा मुखिया को मिल रहा अपार समर्थन बता रहा है कि समाजवादी कारवां अब विजय पताका फहराने के बाद ही रुकेगा।

श्री अखिलेश यादव ने अपने दौरों के क्रम में हरदोई, मुरादाबाद, आगरा, बुलंदशहर, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया एवं व्यापक जनसंपर्क किया।

पश्चिम से पूरब तक के दौरे के दौरान जिस तरह लोगों में श्री अखिलेश यादव की एक झलक पाने की बेताबी दिखी, लाखों लोगों ने अखिलेश यादव के जयकारे लगाए, स्वागत किया, वह बता रहा है कि अखिलेश यादव की शालीनता, सहजता के लोग किस कदर कायल हैं। लोगों का समाजवादी पार्टी का साथ देने का वायदा, अखिलेश यादव की प्रशंसा से समाजवादियों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं।

चुनावी समर से पहले यूपी के दौरों पर निकले श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक तरह से चुनावी

समर का शंखनाद कर दिया है। चुनावी शंखनाद सुनकर समाजवादी भी एकजुट होकर जिस तरह तैयारियों में जुटे हैं उससे साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की राजनीति की दिशा तय करने वाली है।

पश्चिम से पूरब की अपने दौरों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, किसानों व व्यापारियों की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह समझा भी रहे हैं कि किस तरह इन समस्याओं से लोगों को उबारना है। दौरों के दौरान जिस तरह लोगबाग सपा मुखिया से मिल रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उनसे उम्मीद लगा रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि इस चुनाव में लोगों का रुझान समाजवादियों को जिताकर 2024 में सत्ता की चाबी श्री अखिलेश यादव को ही सौंपना है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया का समाज के प्रति स्पष्ट नजरिया, विकासपरक विजन, सभी वर्गों-समुदायों को साथ लेकर चलने की नीति की झलक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में भी दिख रही है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी मुखिया श्री अखिलेश यादव ने साफ संदेश दिया है कि यही ऐसी पार्टी है जोकि समाज के सभी वर्गों, समुदायों को साथ लेकर चलने में न सिर्फ यकीन रखती है बल्कि उसपर अमल भी करती है।

पश्चिम से पूरब तक चंद दिनों के दौरों में ही समाजवादी पार्टी को एहसास हो गया है कि जनता उसे बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। हरदोई से वाराणसी तक के दौरों में आमजन के समर्थन को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने चुनावी समर का शंखनाद करते हुए साफतौर पर संकेत दे दिए हैं कि जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करें और उन्हें इस सरकार की नीतियों से निजात दिलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दें। अपने अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनावी समर के लिए कमर कस चुके हैं।

हरदोई में अखिलेश की झलक पाने की बेताबी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने 3 फरवरी को हरदोई से यूपी दौरे की शुरुआत की। जैसे ही सपा

मुखिया लखनऊ से निकले, रास्ते में उनका जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ता उनकी झलक पाने के लिए बेताब रहे। आमजन भी सड़को के किनारे खड़े होकर अखिलेश जिंदाबाद का नारा लगाते दिखे। जैसे-जैसे श्री अखिलेश यादव का काफिला आगे बढ़ता गया, गाड़ियों का तांता लग गया। हरपालपुर के बैठापुर में एक शादी समारोह में पहुंचते-पहुंचते श्री अखिलेश यादव का काफिला कारवां में तब्दील हो चुका था। बैठापुर में श्री यादव ने शादी समारोह में शिरकत की और वहां कार्यकर्ताओं से बात की। आमजन से मुखातिब हुए तो लोगों ने उनसे अपनी समस्याएं गिनानी शुरू कर दीं। लोग चाहते थे कि वह सरकार में जल्द आएं ताकि उन्हें राहत मिले। सबने भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव 2024 में वह सब उनके साथ हैं।

आजम खान ने किया भव्य स्वागत

प्रशासन ने हवाई जहाज उतरने की अनुमति नहीं दी तो इरादे के पक्के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव वाया बरेली 4 फरवरी को मुरादाबाद पहुंच गए। बरेली से सड़क मार्ग से मुरादाबाद जा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का रामपुर में राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान ने हजारों समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। रामपुर से श्री खान को साथ लेकर श्री यादव मुरादाबाद पहुंचे और उन्होंने वहां पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के सुपुत्र के शादी समारोह में शिरकत की।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 फरवरी को मुरादाबाद पहुंचना था। पार्टी ने प्रोटोकाल के तहत एक फरवरी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का कार्यक्रम प्रशासन को भेज दिया था पर प्रशसन ने मूढ़ा पाण्डेय हवाई पट्टी पर श्री यादव के हवाई जहाज को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। तब, श्री यादव ने फैसला किया कि वह मुरादाबाद जरूर पहुंचेंगे। वह हवाई जहाज से बरेली पहुंचे। यहां हजारों की संख्या में लोगों ने श्री यादव का स्वागत किया। वहां से सड़क मार्ग से मुरादाबाद रवाना हुए तो रास्ते भर उनका स्वागत, जयकारा लगता रहा। रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान ने उनका भव्य स्वागत किया। मुरादाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारों और फूलमालाओं से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का स्वागत

माँ कामाख्या एडवरटाइजर्स
LG

पूरब से पश्चिम तक लहराएगा सपा का परचम

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अब कोई प्रयोग या नया गठबंधन नहीं होगा। जो साथी, साथ हैं उनके साथ ही अकेले दम पर समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। श्री यादव ने विश्वास के साथ कहा है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराया था, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी पूरब से पश्चिम तक समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 9 फरवरी को गाजीपुर के सकरा जैदपुरा ग्राम के लुटावन ग्रुप आफ इन्टर कालेज में पूर्व मंत्री दिवंगत कैलाश नाथ यादव की मूर्ति का अनावरण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। पूर्व मंत्री दिवंगत कैलाश यादव के पुत्र विधायक डॉ वीरेन्द्र यादव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का भरोसा है किसानों, नौजवानों की बदौलत गरीबों को धोखा देने वाली और विनाश करने वाली भाजपा का सफाया होगा क्योंकि देश और प्रदेश की दशा समाजवादी ही सुधार सकते हैं।

विशाल जनसभा में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों को विरासत में समाजवादी आंदोलन मिला है। हमारे नेताओं ने जो समाजवादी आंदोलन दिया है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।

जनसभा में भाजपा पर हमलावर होते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकास नहीं विनाश की ओर ले जा रही है। जनता को धोखा देने और दिखावे के लिए उद्योगपतियों से एमओयू किया जा रहा है। यह सरकार ऐसी-ऐसी कंपनियों से एमओयू कर रही है जो एक कमरे में चल रहे है। आजकल जो भी सूट और टाई में दिख रहा है, भाजपा सरकार उससे एमओयू कर ले रही है। जनता जानना चाहती है कि सरकार बड़े-बड़े सपने दिखा रही है लेकिन विकास और रोजगार कब दिखाई देगा?

उन्होंने कहा कि भाजपा जाति-धर्म के आधार पर भेदभाव करती है। लोकतंत्र और संविधान में कही नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। भाजपा सरकार समाजवादियों पर झूठे मुकदमें लगाकर परेशान कर रही है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।

उन्होंने सवाल पूछा कि कुछ लोगों का कारोबार बढ़ रहा है तो किसानों की आय क्यों नहीं दुगनी हुई। नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिला।

॥ जय सिया राम ॥

लस्सी
शॉप
शुभअवसरों पर
दही और लस्सी के
लिए सम्पर्क करें।

किया। यहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए आमजन की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाया।

आगरा में भाजपा पर हमलावर हुए सपा अध्यक्ष

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का 5 फरवरी को आगरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के पुराने साथी के यहां शादी समारोह में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए उमड़ी भीड़ देख लग रहा था कि पूरा आगरा अपने नेता की झलक पाने को उमड़ पड़ा है। सभी श्री यादव से हाथ मिलाने चाहते थे, अपनी पीड़ा बयान करना चाहते थे। श्री यादव ने सभी को वक्त दिया। आमजन ने बताया कि वह महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। समाजवादी लोग ही महंगाई व बेरोजगारी पर काबू पाने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि अखिलेश सरकार में उन्हें बहुत फायदा पहुंचा। वह सरकार विजन वाली थी। सभी ने भरोसा दिया कि वह समाजवादी पार्टी के साथ हैं क्योंकि उन्हें अखिलेश जी पसंद हैं, अखिलेश जी की विकासपरक सोच ही यूपी को आगे ले जा सकती है।

यहां मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री यादव ने भाजपा सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला बोला। इंवेस्टर मीट से लेकर किसानों की समस्याओं पर श्री अखिलेश यादव ने तर्कसंगत तरीके से अपनी राय रखी।

बुलंदशहर में शरद पवार से मुलाकात

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को रिश्ता निभाना भी बखूबी आता है। राजनीतिक मित्र एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव केके शर्मा की बेटी की शादी में शिरकत के लिए बुलंदशहर पहुंचे श्री अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया। यहां उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष श्री शरद पवार से भी गर्मजोशी से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने पटेलनगर पहुंचे श्री अखिलेश यादव का चंदेरू के निकट दरियापुर गांव के पास से स्वागत का सिलसिला शुरू किया तो वह पूरे रास्ते चलता ही रहा। शादी समारोह में पहुंचकर श्री यादव ने श्री शर्मा की बेटी को आशीर्वाद दिया।

बलिया में पीड़ित परिवार का हौसला बढ़ाया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर संवेदनशीलता का परिचय दिया। 9 फरवरी को बलिया दौरे पर पहुंचे श्री अखिलेश यादव ने सूदखोरों के आतंक से त्रस्त आकर आत्महत्या करने वाले असलहा व्यापारी

नंदलाल के परिवारीजनों से मुलाकात की। उन्होंने पहले नंदलाल को श्रद्धांजलि दी। व्यापारी की पत्नी मोनी गुप्ता को श्री यादव ने आश्वस्त किया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। बच्चों के पालन पोषण के लिए पार्टी सहयोग राशि देगी। बाद में उन्होंने पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राम इकबाल सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर उत्साहित कार्यकर्ताओं से श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता त्रस्त है, उसे समाजवादी पार्टी से ही उम्मीद है इसलिए उसकी समस्याओं को लेकर संघर्ष करें। बलिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया कि असलहा कारोबारी के आत्महत्या करने के मामले को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा ताकि भविष्य में किसी व्यापारी के बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि दिवंगत नंदलाल के तीन मंजिला मकान की जबरन कराई गई रजिस्ट्री को वह निरस्त कराने का प्रयास करेंगे। श्री यादव, छात्र नेता मनीष दूबे मनन के निधरिया स्थित आवास पर पहुंचे और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की।

काशी विश्वनाथ में लोक कल्याण के लिए अभिषेक

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने लोक कल्याण के लिए 10 फरवरी को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने काशी विश्वनाथ में दर्शन-पूजन के साथ अभिषेक भी किया। बड़ों का आशीर्वाद लिया। काशी धाम का दर्शन करने के बाद कहा कि मां गंगा की सफाई कहां हुई? बिना गोमती, वरुणा, यमुना की सफाई के मां गंगा की सफाई नहीं हो सकती है। वरुणा नदी और गोमती नदी की सफाई का कार्य समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। उसे भाजपा ने बर्बाद कर दिया है। श्री अखिलेश यादव ने पप्पू की कुल्हड़ की चाय पी। वह एक मिठाई की दुकान पर भी गए। वहां लोगों ने उनसे मुलाकात की।

मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के दौरान उन्होंने प्रार्थना की है कि आम लोगों का जीवन बेहतर हो। उन्होंने कहा कि यहां जिस कॉरिडोर बनने की चर्चा है उसका प्रस्ताव समाजवादी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आया था। इसके लिए मकान अधिग्रहण का काम भी शुरू हुआ था। भाजपा ने स्थल की सुंदरता, हेरिटेज और इतिहास सबको बर्बाद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि विश्वनाथ धाम परिसर में एक बड़ा पुराना वृक्ष था, उसे क्यों गिरा दिया गया?

जातीय जनगणना

समाजवादी जगाएंगे अलख

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना कराने की अपनी मांग के समर्थन में अब जन जागरण अभियान एवं आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है। पार्टी ने तय किया है कि गांव-गांव जाकर इस मुद्दे पर अलख जगाएगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने हाल ही में गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इसके स्पष्ट संकेत दिए कि जातीय जनगणना की मांग के तहत सपा गांव-गांव आंदोलन करेगी।

श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग पर बल देने के लिए अब ब्लाक स्तर तक अभियान चलाएगी। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉ0 राजपाल कश्यप विभिन्न जनपदों में विधानसभा के ब्लाक स्तर पर संगोष्ठियां कर अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी जातियों की जातिवार जनगणना की मांग पर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। प्रत्येक जिलों में विधानसभा के ब्लाक स्तर पर संगोष्ठी का प्रथम चरण 24 फरवरी 2023 से प्रारम्भ होकर 5 मार्च

2023 तक चलेगा। इसमें 24 व 25 फरवरी को वाराणसी, 26 व 27 फरवरी को सोनभद्र, 28 फरवरी और 01 मार्च को मिर्जापुर, 02 व 03 मार्च को भदोही में संगोष्ठियां होंगी। 4 व 5 मार्च 2023 को प्रयागराज में इस कार्यक्रम का समापन होगा।

समाजवादी पार्टी लगातार यह कहती रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, भागीदारी व हिस्सेदारी देना ही संवैधानिक व्यवस्था व मौलिक अधिकार तथा नैसर्गिक न्याय के दायरे में आता है।

समाजवादी पार्टी की तर्कसंगत एवं जायज मांग को मानने के बजाय भाजपा सरकार पिछड़े वर्गों के वास्तविक आंकड़े को छिपाना चाहती है और उन्हें सत्ता के अधिकार व सम्मान से वंचित रखना चाहती है। दरअसल भाजपा सरकार पिछड़े वर्गों को धोखा दे रही है। वर्ष 2011 में एससी, एसटी,धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ ट्रान्सजेण्डर व दिव्यांग की जनगणना कराकर उनकी जनसंख्या की घोषणा 15 जून, 2016 को ही कर दी गयी थी लेकिन पिछड़ी जातियों की नहीं की गई थी।

यूपीए-2 में कांग्रेस सरकार में पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने का सवाल लोकसभा में सपा संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी तथा श्री शरद यादव जी ने जोरशोर से उठाया था तथा लोकसभा में सभी पिछड़े वर्गों के सांसदों ने समर्थन किया था। सरकार ने जातीय जनगणना कराने का आश्वासन भी दिया लेकिन जब जनगणना करायी गयी तो ओबीसी को दरकिनार कर दिया गया।

कांग्रेस के ही रास्ते पर चलते हुए मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने से मुकर गयी। जबकि सबको मालूम है कि दलित-पिछड़ी जातियों की वास्तविक जनसंख्या आए बिना योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। वास्तविक जनसंख्या स्पष्ट न होने से उनके हक में कोई सकारात्मक आदेश नही हो पाता।सरकारें जानबूझकर दलितों एवं पिछड़ों के अधिकारों के मामलों को दबा देती हैं। 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना कराने के बाद आज तक केन्द्र सरकार ने जातीय जनगणना कराना उचित नहीं समझा।

दलितों और पिछड़ों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुरक्षा व उनके अधिकारों को संरक्षण देना सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार इस जिम्मेदारी से हट रही है।

हक व सम्मान के लिए जातीय जनगणना जरूरी

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का स्पष्ट मत है कि पिछड़ों, दलितों को हक और सम्मान दिलाने के लिए जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि जातीय जनगणना होने के बाद सभी जातियों का आंकड़ा सामने आ जाएगा और उसी के मुताबिक योजनाएं बनाने में आसानी होगी। तब, योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना हो जाने के बाद समाज से अन्याय व भेदभाव भी खत्म होगा।

यूपी के दौरों पर निकले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने बेबाकी से जातीय जनगणना पर अपनी राय रखी है और जागरुकता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछड़ों और दलितों को उनका वास्तविक हक और सम्मान दिलाने के लिए लंबी समय से समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग कर रही है लेकिन भाजपा सरकार इसका विरोध कर रही है क्योंकि भाजपा जातीय जनगणना से डरती है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा सरकार लगातार पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा कर रही है। साजिश के तहत पिछड़ों, दलितों के आरक्षित पद भाजपा सरकार खत्म करने पर तुली है। उनका मानना है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए रणनीति के तहत निजीकरण को बढ़ाया दिया जा रहा है। सरकारी विभागों में निकलने वाली भर्तियों में कोई न कोई बहाना कर पिछड़ों और दलितों को रोका जा रहा है। बाद में इन पदों पर भाजपा सरकार अपने चहेतों का चयन कर ले रही है।

श्री यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की विरोधी भाजपा हर कदम पर दलितों, पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रही है। पीजीआई लखनऊ में पिछले दिनों आरक्षण के नियमों को दरकिनार कर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को रिक्त छोड़ दिया गया। प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में भी दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा की गई । उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पिछले वर्षों में हुई नियुक्तियों में भाजपा सरकार ने पिछडों, दलितों को उनका हक नहीं दिया। 69 हजार शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता करते हुए पिछड़ों को उनका हक नही दिया गया।

जातीय जनगणना

राष्ट्र निर्माण की बुनियादी जरूरत

डॉ लक्ष्मण यादव

देश किसी भौगोलिक चौहद्दी का नाम नहीं है। मुल्क़ किन्हीं लक़ीरों के ज़रिए घेर दी गई बस्तियों के समूह से नहीं बन जाता। राष्ट्र मात्र जनसंख्या नहीं होता। देश, मुल्क़ या राष्ट्र अपने नागरिकों से बनता है। आधुनिक राष्ट्र राज्य की लोकतांत्रिक संकल्पना समता व न्याय पर आधारित है। कोई भी मुल्क़ अपने नागरिकों में समता व न्याय स्थापित किए बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। थोड़े से लोगों के पास संसाधन, अवसर और सम्मान बहुत ज़्यादा हों और देश की बहुत बड़ी आबादी के पास बेहद कम हों या न हों, यह एक देश के सामने चुनौती होती है। एक देश ऐसी तमाम अन्यायपूर्ण ग़ैर-बराबरियों से लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। डॉ आम्बेडकर ने इन्हीं पृष्ठभूमियों में भारत को एक 'बनता हुआ राष्ट्र' कहते हुए राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अंतर्विरोधों की चेतावनी भी दी थी। समाजवादी आंदोलनों के तो नारे ही रहे कि 'सौ से कम न हज़ार से ज़्यादा, समाजवाद का यही तक़ाज़ा', 'मिटे ग़रीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी'। समानता व

न्याय के लिए वास्तव में इच्छुक देश के लिए सबसे प्राथमिक ज़रूरत है अपने नागरिकों से संबंधित वैध व तथ्यपरक प्रामाणिक आंकड़े जिससे कि वह देश के नागरिकों के बीच हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों की प्रकृति को समझ कर कारगर नीति निर्धारण करते हुए निर्णय ले सके।

जातीय जनगणना के बिना प्राप्त आंकड़े अधूरे होते हैं। 1931 की अंतिम जनगणना में जब जातियों को भी गिना गया था, तब इस देश को पता चल सका कि इस देश में कौन कौन सी जातियां कितनी शिक्षा, रोज़गार, संसाधन, ज़मीन का मालिकाना हक़ या संपन्नता पा सकीं। ग़रीबों में सबसे हाशिए पर कौन है? बेघर कौन लोग हैं? अशिक्षित कौन सबसे ज़्यादा रह गया?

बिना जातियां गिने सबसे वंचित शोषित जमात की पहचान अधूरी रह जाती है। ऐसे में कोई भी सरकार समता व न्याय स्थापित करने के लिए बजट आवंटन से लेकर शिक्षा, रोज़गार, छात्रवृत्ति जैसे विशेष प्रावधानों को बनाने में विफल ही रहेगी। किनके लिए, कैसे और कितनी योजना बनानी है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। यह जानकारी मुहैया कराने का सबसे वैध व सार्थक उपक्रम है जातीय जनगणना।

आज़ादी के बाद एक संकल्पना यह आई कि हम नए भारत को जाति, धर्म, भाषा, लिंग जैसे किसी भी विभाजन से मुक्त बनाएंगे। मगर दिलचस्प है कि धर्म, लिंग, भाषा सब कुछ जनगणना में गिने जाते रहे। एससी और एसटी में आने वाली जातियां भी गिनी जाती रहीं मगर ओबीसी और सवर्णों को गिनने से परहेज़ किया गया।

भारत जैसे देश को समता व न्याय पर आधारित बनाने के लिए सबके बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए जातीय जनगणना का अर्थ है सभी जातियों की गिनती। हाल ही में आई ऑक्सफ़ेम की रिपोर्ट बताती है कि इस देश के एक फ़ीसदी लोगों के पास इस देश के 40.5 फ़ीसदी संसाधन हैं और तक़रीबन पचास फ़ीसदी आबादी तीन फ़ीसदी संसाधनों से गुज़ारा कर रही है। यह जानना ज़रूरी है कि ये एक फ़ीसदी कौन हैं और पचास फ़ीसदी कौन हैं? यूं ही नहीं भारत के संविधान निर्माण के समय से लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार करते हुए लगातार जातीय जनगणना की मांग की जाती रही है।

भारत में किसान, कामग़ार, कारीगर, हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों में लगे हुए मेहनतकश कमेरा लोगों की कुल आबादी कितनी है, यह नहीं पता। 1931 की जातिगत जनगणना में आखिरी बार ओबीसी की आबादी प्रकाशित की गई थी, जहां इसे देश की आबादी का 52 फ़ीसदी बताया गया था। कालांतर की किसी भी सरकार ने ओबीसी की गणना के लिए इस तरह की कवायद नहीं की है।

दलितों और आदिवासियों जैसे अन्य वंचित शोषित सामाजिक समूहों की जातीय जनगणना की जाती है लेकिन ओबीसी की

उपस्थिति के बारे में कोई राष्ट्रीय स्तर का डेटा नहीं है जबकि 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफ़ेसर ओबीसी का नहीं था। न्यायपालिका, प्रशासनिक क्षेत्र से लेकर अकादमिक जगत में कमोबेश यही हक़ीक़त है।

जातीय जनगणना के ज़रिए विभिन्न राज्यों से लेकर केंद्रीय संस्थानों तक में उनकी वास्तविक भागीदारी के बारे में ठोस आंकड़े उपलब्ध होंगे जिनका सार्थक प्रयोग हो सकेगा। अनिश्चित व अपर्याप्त सामाजिक आंकड़ों की स्वीकृति के साथ, सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल दिए गए समूहों के बीच एक नई राजनीतिक चेतना उभर सकती है, जो उन्हें सामाजिक न्याय के लिए एक व्यापक व सार्थक जन-आंदोलन का आग़ाज़ के लिए मजबूर कर सकती है। सरकारें संसाधनों व अवसरों के इस बेइंतहा ग़ैर-बराबरी को छुपाना चाहती हैं ताकि वर्चस्वशाली तबक़ों के सामाजिक, आर्थिक वर्चस्व को बरकरार रखा जा सके। ऐसा करना किसी भी समाज व देश के लिए बेहद चिंताजनक है।

1901 की जनगणना में चिह्नित की गई जातियों की संख्या 1,646 थी, जो 1931 की जनगणना में बढ़कर 4,147 हो गई, जो भारत में जाति आधारित अंतिम जनगणना के आंकड़े हैं। हालांकि, जातियों की कुल संख्या में 300 से अधिक ऐसी जातियां भी शामिल हैं जिनका धर्म ईसाई धर्म के रूप में दर्ज किया गया और 500 से अधिक वे जातियां हैं, जिन्हें मुस्लिम के रूप में दर्ज किया गया।

वहीं दूसरी ओर, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने के. एस. सिंह के नेतृत्व में 'पीपल ऑफ इंडिया' प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो 1990 के दशक में पूरा हुआ। इस अध्ययन के अनुसार भारत में 4,635 जातियां या समुदाय हैं। केंद्रीय सूची में 2,479 ओबीसी जातियां हैं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक साथ सूची के अनुसार 3,150 ओबीसी जातियां हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने ओबीसी की गिनती को लेकर बेहद चिंता जताई। कमीशन ने 1931 की जातिगत जनगणना के साथ कुछ सर्वे का इस्तेमाल करते हुए ओबीसी की सूची में 3743 जातियों को शुमार किया।

आज 2023 में यह बेहद ज़रूरी है कि देश भर की सभी जातियों के वास्तविक आंकड़े जुटाएं जाएं। ये आंकड़े भारत की एक ऐसी वास्तविक तस्वीर बयान करेंगे, जिसके बाद यह सुनिश्चित करने में सुविधा होगी कि किन सामाजिक समूहों को ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हासिल हो चुका है और किन्हें न्यूनतम भी हासिल न हो सका। यह जाने बग़ैर एक बराबरी का मुल्क़ बना पाना असंभव है।

जातीय जनगणना की मांग लगातार होती रही है। प्रधानमंत्री रहते हुए श्री देवगौड़ा ने 2001 की जनगणना के साथ जातीय जनगणना का प्रावधान पास कर दिया जिसे बाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नामंज़ूर कर दिया। 2010 में एक बार फिर

जातीय जनगणना का मुद्दा भारतीय राजनीति में गूंजता है, जब संसद में तमाम समाजवादी नेताओं व बहुजन नेताओं के भारी दबाव के चलते 2011 की जनगणना में जातियों को गिनने की बात माननी पड़ी मगर तत्कालीन सरकार ने इसके इतर समजैक-आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) करवाने की चाल चल दी। हालांकि उसके आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए।

23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में मौजूदा केंद्र सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जातिगत जनगणना अव्यावहारिक, प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है जबकि परंपरागत रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जातिगत जनगणना होती रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शैक्षिणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 द्वारा घोषित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने माना कि 1931 की जनगणना ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक निर्धारक कारक नहीं हो सकती है और केंद्र सरकार से यह निर्धारित करने के लिए कहा कि कौन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

जातीय जनगणना से जातिवाद बढ़ने के बजाय ख़ात्मे की तरफ़ बढ़ेगा क्योंकि सबको सबके हिस्से का संसाधन, अवसर व सम्मान मिलना सुनिश्चित होगा। जातीय जनगणना भारत को जोड़ने के साथ ही सभी वंचित शोषित समुदायों के लिए एक नया अध्याय लेकर आएगी। ये गणना भारतीय राजनीति को तमाम विभाजनकारी मुद्दों से बचाकर पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई पर आधारित सकारात्मक परिवेश मुहैया कराएगी। गणना से नुक़सान उन्हीं का है, जिन्होंने अपने हिस्से से ज़्यादा जगहें घेर रखी हैं मगर फ़ायदा पूरे मुल्क़ का होगा। समता व न्याय केवल क़िताबी लफ्ज न होकर रह जाएं, संविधान व मंडल कमीशन की सिफ़ारिशें अधूरी क्रांति बनाकर न रह जाएं, मानवता इंसान के सामाजिक आर्थिक हैसियत से तौली जाती रहने वाली शै' बनकर न रह जाए, इस सबका तक़ाज़ा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर एक आंदोलन छेड़ दिया जाए।

आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर दावा झूठा है, अगर वह सबको बराबर का न्याय व हिस्सा न दे सके। जातीय जनगणना दरअसल जातिगत ग़ैर-बराबरी के खिलाफ व हिस्सेदारी के लिए ज़रूरी एक क्रांति की आवश्यकता मात्र नहीं है, यह भारत को सबका बराबर का आधुनिक व मुकम्मल मुल्क बना देने वाली कोशिश का पर्याय है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

फोटो स्रोत : गूगल

सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना जरूरी

राजकुमार भाटी

भारत का संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की गारंटी देता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में व्याप्त जातिगत ऊंच नीच और गैर बराबरी को दूर करना। इस गैर बराबरी के कारण इतिहास में छिपे हैं। यह देश हजारों वर्षों तक उस आर्थिक सामाजिक व्यवस्था से संचालित हुआ है जिसमें समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा, सम्पत्ति और सम्मान से वंचित रखा गया।

चार वर्ण और चार हजार से अधिक जातियों में बंटे समाज की 85 प्रतिशत आबादी को पढ़ने-लिखने, सम्पत्ति अर्जित करने, शक्ति व सत्ता प्राप्ति के प्रयास करने और सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने से यत्नपूर्वक रोका गया। इस अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण समाज का

बड़ा वर्ग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ता चला गया।

भारत के नीति निर्माताओं ने यह महसूस करके कि हजारों वर्षों की विभेदकारी नीतियों के चलते भारतीय समाज के कुछ हिस्से अत्यंत पिछड़ गये हैं, संविधान में उन वर्गों के लिये विशेष अवसरों के प्रावधान किये थे। भारत के संविधान में देश के नागरिकों को उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों के आधार पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग चार श्रेणियों में बांटा गया है।

सामाजिक अन्याय का शिकार रहे इन वर्गों को इस अन्याय से उबारने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गयी। इस व्यवस्था के तहत एससी को 16 प्रतिशत, एसटी को 6 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सामान्य जाति के गरीबों का एक पांचवा वर्ग बनाया जिसे संक्षेप में EWS (इकॉनामिक वीकर सेक्शन) कहा जाता है। इस वर्ग के लिए शिक्षा व सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया है।

सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिये संविधान में किये गए प्रावधानों को कभी भी ईमानदारी से लागू नहीं किया गया।

नतीजा, आजादी के 75 वर्ष बाद अभी तक भी इन वर्गों का कोटा सरकारी नौकरियों में पूरा नहीं हो पाया। 15 दिसम्बर 2022 को सरकार की ओर से दिये गये एक जवाब के अनुसार केन्द्र सरकार की सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के कोटे के आधे से भी कम पद अभी रिक्त हैं।

सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग की स्थिति

केंद्र सरकार में दलित समाज के रिक्त पद	
ग्रुप ए	48.5%
ग्रुप बी	60.0%
ग्रुप सी	45.8%

केंद्र सरकार में आदिवासी समाज के रिक्त पद	
ग्रुप ए	53.2%
ग्रुप बी	60.7%
ग्रुप सी	53.3%

केंद्र सरकार में पिछड़े वर्गों के रिक्त पद	
ग्रुप ए	60.9%
ग्रुप बी	74.8%
ग्रुप सी	60.3%

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में उच्च शिक्षा में सेवारत कुल शिक्षकों में मात्र 6.9 प्रतिशत एससी, 1.9 प्रतिशत एसटी और 21.9 प्रतिशत ओबीसी हैं। बसावन इंडिया नामक पत्रिका ने जनवरी 2023 के अंक में उत्तर प्रदेश के सभी 3 6 विश्वविद्यालयों में कार्यरत उपकुलपतियों का वर्गवार विश्लेषण करके एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार 36 उपकुलपतियों में 26 सामान्य वर्ग के हैं। एक अन्य विश्लेषण के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नियुक्त उच्च अधिकारियों में 63 प्रतिशत जिलाधिकारी, 65 प्रतिशत पुलिस कप्तान और 73 प्रतिशत बेसिक शिक्षा अधिकारी सामान्य वर्ग के हैं।

2 जनवरी 2023 को केंद्रीय न्याय विभाग ने संसद की स्थाई समिति को एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया है कि विगत 5 वर्ष में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 537 जजों की नियुक्ति हुई। रिपोर्ट के अनुसार इनमें मात्र 11 प्रतिशत ओबीसी, 2.8 प्रतिशत एससी और 1.3 प्रतिशत एसटी वर्ग के है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मातादीन अनुरागी द्वारा मांगी गई सूचना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 5 जनवरी 2018 को लिखित जवाब में बताया था कि देश के कुल 496 उपकुलपतियों में अनुसूचित जाति के मात्र 6, अनुसूचित जनजाति के 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 36 उपकुलपति हैं जबकि संवैधानिक आरक्षण में निर्धारित कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति के 100, अनुसूचित जनजाति के 25 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 135 उपकुलपति कम से कम होने चाहिये।

देश में सामाजिक न्याय की दयनीय स्थिति को दर्शाने के लिए यहां मात्र कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। लगभग सभी सरकारी विभागों और सभी मंत्रालयों की यही स्थिति है। इसका कारण यह है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की नीयत ठीक नहीं है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी शीर्ष पदों पर विशिष्ट वर्गों का वर्चस्व टूट नहीं पाया है और वंचित वर्गों को उनकी हिस्सेदारी मिल नहीं पायी है।

जवाहर लाल नेहरू ने एक बार डा लोहिया की आलोचना करते हुए कहा था कि लोहिया जी सबको बराबर करना चाहते हैं किन्तु क्या यह सम्भव है, उन्होंने अपना पंजा दिखाते हुए कहा - "देखो ईश्वर ने हाथ की सारी उंगलियां भी बराबर नहीं बनायी हैं।"अगले दिन लोहिया जी ने अपनी जनसभा में इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होने कहा -" मैं मानता हूॅ कि ईश्वर ने हाथ की सारी उंगलिया बराबर नहीं बनाई किंतु हाथ की एक उंगली यदि एक फुट लम्बी और दूसरी एक इंच लंबी हो तो कभी उस हाथ की मुट्ठी नही बंध सकती।"

हाथ और उंगलियों के रूपक से कही गयी लोहिया जी की यही बात देश पर लागू होती है। देश का यदि एक वर्ग बहुत विकसित हो और दूसरा पिछड़ा तो वह देश कभी मजबूत नही हो सकता।

देश का कौन सा हिस्सा किस बात में पिछड़ा

है, कमजोर है, अविकसित है इसे जानने का सबसे उपयुक्त तरीका जातीय आधारित जनगणना है। जनगणना केवल सिरों को गिनने भर की कार्यवाही नही होती। उसमें एक- एक नागरिक के हर पहलू शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके रहन सहन संबंधी सभी जानकारियां एकत्र की जाती हैं। जनगणना में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही सरकारें अपनी योजनाएं बनाती हैं।

जातीय आधारित जनगणना के बाद ही हम यह जान पाएंगे कि समाज के किस हिस्से को शिक्षा संबंधी सुविधाएं ज्यादा चाहिए किसे स्वास्थ संबंधी। किसे रोजगार की ज्यादा आवश्यकता है और किसे खेल अथवा मनोरंजन की। यदि हम प्रमाणिक आंकड़ों के बिना सामाजिक विकास की योजनाएं बनाते हैं तो वह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई डाक्टर बिना जॉच किये रोगी की चिकित्सा प्रारम्भ कर दे।

देश में जो लोग सामाजिक न्याय के विरोधी हैं वे जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ तरह-तरह के कुतर्क पेश करते रहते हैं। इनका मुख्य तर्क योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी का होता था किन्तु जिस दिन से ईडब्लूएस का आरक्षण लागू हुआ है इन्होने योग्यता का प्रश्न उठाना बन्द कर दिया है। वर्तमान समय में अधिकांश सरकारी भर्तियों में ईडब्लूएस की कट ऑफ ओबीसी से नीचे जा रही है। इसका अर्थ है कि सामान्य जातियों के प्रतियोगी कम अंक पाकर नियुक्त हो रहे हैं और ओबीसी के उम्मीदवार उनसे ज्यादा अंक लाकर भी नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं।

आरक्षण विरोधियों का दूसरा कुतर्क यह होता है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी। अब इसे बंद कर देना चाहिए। समय-समय पर आरक्षण की समीक्षा का प्रश्न भी उछाला जाता है।

जातीय जनगणना के बाद ही हम यह जान पाएंगे कि समाज के किस हिस्से को शिक्षा संबंधी सुविधाएं ज्यादा चाहिए किसे स्वास्थ संबंधी। किसे रोजगार की ज्यादा आवश्यकता है और किसे खेल अथवा मनोरंजन की

पहली बात तो 10 वर्ष की अवधि राजनैतिक आरक्षण के लिए थी, शिक्षा व सेवाओं में आरक्षण के लिए नही। दूसरे यदि आरक्षण की समीक्षा की जानी है तो उसके लिए हमारे पास जातियों की जनसंख्या और नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व के प्रमाणिक आंकड़े होने चाहिए। यह आंकड़े जाति आधारित जनगणना से ही मिल सकते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को ठीक से लागू करने के लिए जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है।

सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के लिए निर्धारित की गयी 50 प्रतिशत की सीमा टूट चुकी है। नई परिस्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग की इस मांग को पूरा करने में कोई रुकावट नही है कि उनका आरक्षण कोटा उनकी आबादी के अनुपात में होना चाहिए। देश की कुल आबादी में ओबीसी का अनुपात कितना है इसका कोई अधिकृत आंकड़ा सरकार के पास नही है। सब अपनी- अपनी सुविधा के हिसाब से आंकड़े पेश करते हैं। आरक्षण विरोधी कहते हैं कि ओबीसी की आबादी 40 प्रतिशत है, ओबीसी कहते हैं कि वे 60 प्रतिशत से ज्यादा हैं। जातिगत जनगणना के बाद यह विवाद भी समाप्त हो जाएगा। लिहाजा सामाजिक न्याय के मद्देनजर देश में जाति आधारित जनगणना होना बहुत जरूरी है।

(लेखक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं)

फोटो स्रोत : गूगल

राजनीति वही जो लोकतंत्र को बचाए

अरुण कुमार त्रिपाठी
वरिष्ठ पत्रकार

जातिवाद यानी वर्णाश्रम धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था तो बहुत पुरानी है लेकिन 33 साल पहले शुरू हुई नवउदारवादी नीतियां भी अट्ठारहवीं सदी की मुक्त व्यापार की नीतियों का ही नया रूप थीं। जितनी पुरानी यह नीतियां हैं उतनी ही पुरानी है उनसे लड़ाई लड़ने की परंपराएं। कभी यह लड़ाइयां तेज हो जाती हैं तो कभी मद्धिम। जब लड़ाइयां तेज होती हैं तो इंसानी बराबरी और भाईचारा बढ़ता है और जब कमजोर हो जाती हैं तो वह बिगड़ जाता है। आज दूसरी प्रक्रिया घटित हो रही है।

आज भारतीय लोकतंत्र के साथ जो कुछ हो रहा है वह अचानक नहीं हुआ है। इसका खतरा तब जताया गया था जब इस देश में नवउदारवादी नीतियां शुरू की गई थीं। समाजवादी चिंतक किशन पटनायक ने साफ शब्दों में चेताया था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने, सोमनाथ से अयोध्या तक आडवाणी जी की रथयात्रा होने और उसके बाद डंकल प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना और नवउदारवाद का

लागू किया जाना यह सब अलग अलग होने वाली घटनाएं नहीं थीं। इनके बीच एक गहरा रिश्ता था। किशन पटनायक ने `गुलामी का खतरा' जैसी पुस्तिका प्रकाशित कर यह बताया था कि जब पिछड़ों को आरक्षण देने वाली मंडल आयोग की रपट लागू की गई तो सवर्ण समाज बेचैन हो उठा। उसे शांत करने के लिए अयोध्या आंदोलन तेज किया गया। राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया और राजनीति और धर्म को एक कर दिया गया। अल्पसंख्यकों को समान शत्रु बताकर हिंदू समाज को गोलबंद किया गया। लेकिन इतने से भी बात नहीं बन रही थी तो उदारीकरण की प्रक्रिया तेज की गई।

इस तरह मंडल आयोग की रपट से अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों (एक हद तक अल्पसंख्यकों का भी) का जो सबलीकरण हुआ था उसकी काट के रूप में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू की गई। सरकार की ओर से जनता को दी जाने वाली रियायतें वापस ली जाने लगीं। जनता की चुनी हुई संस्थाएं बेअसर होने लगीं और मुक्त व्यापार की छूट दी जाने लगीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आरक्षण और संपन्नता व बराबरी की लड़ाई समाजवाद के हथियार हैं तो सांप्रदायिकता और निजीकरण पूंजीवाद के शस्त्र।

इस बात को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संबंधी और मैनेजमेंट व राजनीति शास्त्र के गंभीर विद्वान आनंद तेलतुंबड़े ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक आफ कास्ट--- थिंकिंग इक्वेलिटी इन द टाइम आफ नियोलिबरल हिंदुत्व में विस्तार से प्रस्तुत किया है।

जिस नियोलिबरल हिंदुत्व से समता के सपने को कुचले जाते वे देखते हैं उसकी बड़ी तस्वीर हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी के लुढ़कते शेयरों और राष्ट्र की वित्तीय संस्थाओं से की जाने वाली मनमानी के साथ संसद में उच्च राजनीतिक स्तर पर होने वाले अडानी के बचाव के तौर पर देख सकते हैं।

जनता द्वारा चुनी गई संसद के सामने कार्यपालिका की कोई जवाबदेही नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 किसी भी सांसद को जनहित के मुद्दे संसद में उठाने का अधिकार देता है। शर्त यही है कि उसकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए

यह भारतीय लोकतंत्र की कोई मामूली घटना नहीं है कि विपक्ष का नेता सीधे देश के प्रधानमंत्री पर एक जोड़तोड़ और अमानत में खयानत करने वाले पूंजीपति से सांठगांठ करने का आरोप लगाए और प्रधानमंत्री उसका उल्लेख करने से साफ मुकर जाएं। जवाब देने की बात तो दूर वे अडानी का उल्लेख तक नहीं करते। उल्टे यूपीए सरकार पर लगे उन घोटालों का आरोप दोहराने लगते हैं जिनकी अदालती जांच में पुष्टि नहीं हो पाई॥ इतना ही नहीं संसद से विपक्षी नेता की वे टिप्पणियां भी हटा दी जाती हैं जो उन्होंने अडानी संबंधी पूरे विवाद में कही थीं। यानी—

मत कहो आकाश में कोहरा घना है,
यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।

दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ यह भी कहा जा सकता है कि—

यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं,
खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा।

लोकतंत्र का यह जलसा या तो देश की सार्वजनिक संपत्ति को पूंजीपतियों द्वारा लूटे जाने का जलसा हो गया है अथवा उनके पैसे से कुछ राजनीतिक दलों द्वारा वोट के लूट का जलसा बन गया है या फिर गूंगे और बहरे लोगों का जमावड़ा हो गया है। संसदीय प्रणाली एक जीवंत प्रणाली है जिसके बारे में 2014 में स्वयं मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जनता के प्रधान सेवक हैं। लेकिन आज हम उस सेवक से सिर्फ आदेश देने की उम्मीद कर सकते हैं जनता के किसी आदेश के पालन की नहीं।

आदेश के पालन की बात तो छोड़िए उस जनता द्वारा चुनी गई संसद के सामने कार्यपालिका की कोई जवाबदेही नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 किसी भी सांसद को जनहित के मुद्दे संसद में उठाने का अधिकार देता है। शर्त यही है कि उसकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। लेकिन अब तो असंसदीय कह कर उसके भाषण के आवश्यक अंश हटाए जा रहे हैं।

कहा जा रहा है कि पहले अपनी बात का सुबूत दीजिए फिर बात रखिए। यानी अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी विचार को व्यक्त करने की आजादी नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री चाहें जिसका मजाक उड़ाएं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने राज्यसभा के

चेयरमैन को पत्र लिखकर ठीक ही कहा है कि सरकार की नीतियों की आलोचना को किसी की व्यक्तिगत आलोचना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

भारत के विचार पर टिप्पणी करते हुए वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आंबेडकर के आदर्श अब प्रकाश वर्ष की दूरी पर चले गए हैं। हर दिन गुजरने के साथ वे और भी दूर होते जा रहे हैं। उनका मानना है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य तो बना था लेकिन यहां की जाति-व्यवस्था के कारण वह जाति का गणराज्य बन गया। आज समता सार्वजनिक विमर्श में कहीं है ही नहीं।

हाल में विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन में आक्सफैम ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक भारत के सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत से अधिक संपत्ति है जबकि 50 प्रतिशत आबादी के पास महज तीन प्रतिशत संपत्ति है। जातिगत असमानता की स्थिति तो यह है कि इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक को कहना पड़ रहा है कि वर्णव्यवस्था ईश्वर ने नहीं पंडितों ने बनाई। उस पर इस कदर विवाद छिड़ा हुआ है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई शंकराचार्य और महंतों ने कह डाला है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्ण हमने बनाए हैं।

इन्हीं स्थितियों पर तेलतुंबड़े कहते हैं कि विश्व बैंक और हिंदुत्व ब्रिगेड ने मिलकर समता को समावेशिता और समरसता में बदल दिया है। आज भारत दुनिया का सबसे असमान देश हो गया है। एक ओर यहां जाति व्यवस्था की श्रेणीगत असमानता तो थी ही दूसरी ओर पूंजीवाद ने लोगों के बीच आर्थिक खाई कई

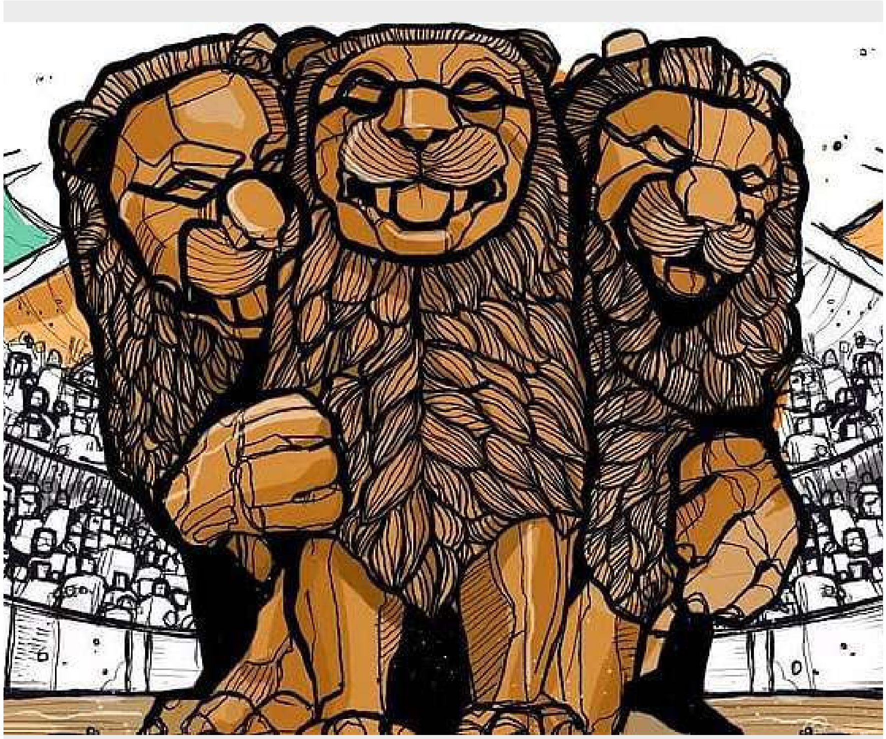

गुना बढ़ा दी है। याद कीजिए डा लोहिया नारा लगाते थे कि लोगों की आय का अंतर एक और दस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज यह बात कहते ही तमाम लोग आप को मूर्ख बताने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि अब यह स्तर करोड़ों गुना हो चुका है। मंदिर आंदोलन के बाद देश का भाईचारा ही नहीं मिटा है बल्कि जो जातिगत समता आ रही थी वह ठहर गई और उल्टे सामाजिक असमानता की हवा बहने लगी।

भारत तीन प्रकार की कट्टरताओं का शिकार हो गया है। एक कट्टरता पूंजी की है जो मानती है कि हम जो करते हैं सही होता है। वह चाहे जिस संस्था से जितना धन ले ले और उसका चाहे जिस तरह से उपयोग करे। अगर सत्ता में बैठे लोगों से उसकी सांठगांठ है तो हमारी निगरानी प्रणाली उस पर हाथ नहीं डालेगी। दूसरी ओर धार्मिक कट्टरता है। अल्पसंख्यक समाज की कट्टरता की बहुत चर्चा होती थी और वह एक हद तक सही भी है। क्योंकि किसी की टिप्पणी कितनी भी आपत्तिजनक हो लेकिन सर तन से जुदा करने का हक किसी को नहीं है। उस पर उस समाज के लोग और प्रगतिशील समाज के दूसरे लोग काम कर रहे थे लेकिन उसी का जिक्र करते करते आज बहुसंख्यक समाज भी कट्टर हो चला है। अब वह अपनी कट्टरता के बचाव में यही कहता है कि जब अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने धर्मग्रंथों या परंपराओं की रक्षा में खड़े होते हैं तो आप कुछ नहीं कहते। जब बहुसंख्यक समाज खड़ा होता है तो उसकी आलोचना की जाती है।

तीसरी कट्टरता जातिगत कट्टरता है। जातियां टूट रही थीं। अंतरजातीय विवाह हो रहे थे। लेकिन मौजूदा माहौल में जाति की कट्टरता बढ़ी है। जातियों को समाप्त करने के लिए जो समाज सुधार आंदोलन और कट्टरता की आलोचना करने वाले विमर्श चाहिए उन पर भावनाएं आहत करने का

आरोप लगाकर उन्हें खामोश कर दिया जाता है। इसलिए जातियों को ढीला करने या तोड़ने का सिलसिला चल नहीं पाता है। धार्मिक ग्रंथों की पंक्तियों पर छिड़े विवाद के साथ भी उदार की बजाय कट्टर मन से ही प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है। किसी की जीभ काट लेने या हत्या करने के लिए इनाम घोषित करने की प्रवृत्ति को आप और क्या कहेंगे?

भारत में जाति और धर्म की कट्टरता ने बाजार से गठजोड़ बना लिया है और वे बहुसंख्यकवाद की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए न तो जाति की असमानता मिटती है और न ही धर्म की। इस प्रवृत्ति के सबसे ज्यादा शिकार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और स्त्रियां होती हैं। मॉब लिंचिंग, आदिवासियों का दमन और स्त्रियों को मार कर टुकड़े टुकड़े करने की घटनाएं इसी गठजोड़ का परिणाम हैं।

भारत में एक ओर हिंदू राष्ट्र के आसन्न खतरे से लड़ना जरूरी है तो दूसरी ओर आर्थिक और जातिवादी असमानता को मिटाना भी आवश्यक है। इसके लिए डॉ भीमराव आंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थलों को तीर्थ बनाने से भला नहीं होगा बल्कि उनके विचारों को अपनाना होगा। इसके लिए डॉ राम मनोहर लोहिया का उल्लेख करते हुए समाजवादी पार्टी को पदच्युत बताने से काम नहीं चलेगा। हमें अगर इस देश और समाज का कल्याण करना है तो उनके विचारों को अपनाना होगा और उन कठिन रास्तों पर चलना होगा जिन पर वे लोग चले थे।

डॉ आंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए घातक होगा। अगर वैसा हुआ तो देश को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। इसी तरह डॉ लोहिया ने कहा था कि किसी एक धर्म को किसी एक राजनीति से कभी नहीं मिलाना चाहिए। इससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है और राजनीति कलही हो जाती है। इसके बावजूद दोनों के बीच संवाद का रिश्ता कायम रहना चाहिए।

समता भी स्तर और अवसर की होनी चाहिए और उसे सभी के भीतर फैलाना चाहिए। जबकि बंधुता में व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता आवश्यक है। डॉ आंबेडकर ने संविधान की उद्देशिका में इन सिद्धांतों को समाहित किया था

आज की राजनीति का तकाजा यह है कि हमें हमारे पुरखों से जो कुछ मिला है उसे कैसे ऊपर के स्तर पर बचाया जाए और उसकी युगानुकूल नई व्याख्या करते हुए कैसे उसे नीचे के स्तर तक पहुंचाया जाए। उदाहरण के लिए हमारा संविधान अगर न्याय की बात करता है तो वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों किस्म के न्याय की कैसे प्रदान कर सकता है। न्याय की परिभाषा यह है कि जो व्यवहार आप अपने साथ न चाहें वह दूसरों के साथ न करें। इसी प्रकार स्वतंत्रता पांच प्रकार की मांगी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और प्रार्थना। इनकी स्वतंत्रता के बिना सारी स्वतंत्रता बेमानी है। समता भी स्तर और अवसर की होनी चाहिए और उसे सभी के भीतर फैलाना चाहिए। जबकि बंधुता में व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता आवश्यक है। डॉ आंबेडकर ने संविधान की उद्देशिका में इन सिद्धांतों को समाहित किया था। आज इन्हें नागरिकों को समझाना और उनकी हिफाजत के लिए तैयार करना है।

यहां जाति और वर्ग के रिश्तों की भी समझ आवश्यक है। भारत में जाति और वर्ग आपस में अंतर्गुंफित हैं। जातियों के विनाश के बिना भारत में कोई क्रांति नहीं हो सकती। उसी प्रकार क्रांति के बिना भारत में जाति का समूल नाश नहीं हो सकता। वह क्रांतियां डॉ लोहिया की सप्तक्रांतियां या जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के रूप में होनी चाहिए। उनका तरीका गांधी के सत्य और अहिंसा का ही होना चाहिए। यानी भावी राजनीति लोकतंत्र को बचाने की होनी चाहिए और उसके लिए जातिगत भेदभाव, पूंजीवादी असमानता और धार्मिक विद्वेष के विरुद्ध मोर्चा लगना चाहिए।

फोटो स्रोत : गूगल

संगोष्ठी में गूंजी जातीय जनगणना कराने की मांग

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने जातीय जनगणना पर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत पूरे प्रदेश में संगोष्ठियों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत 8 फरवरी को हरदोई जनपद से हुई।

समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा राजपाल कश्यप ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर अभियान के रूप में जातीय जनगणना पर संगोष्ठी कराई जाएगी।

हरदोई की संगोष्ठी में जातीय जनगणना की मांग उठाते हुए कहा गया कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, समाज के वंचितों व पिछड़ों का भला नहीं हो सकता। जातीय जनगणना से सही आबादी का पता लगेगा और शिक्षा से लेकर नौकरी तक इस तबके को हक और सम्मान दिलाया जा

सकेगा। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ है और वह पिछड़ों और दलितों को हक और सम्मान नहीं देना चाहती है।

सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 8 फरवरी को गृह जनपद हरदोई पहुंचे डॉ राजपाल कश्यप के स्वागत समारोह के बाद जातीय जनगणना कराने के समर्थन में यह संगोष्ठी हुई। 'जातीय जनगणना' पर अपनी राय रखते हुए डॉ राजपाल कश्यप ने कहा कि पिछड़ी जातियों की सही जानकारी और आंकड़े पता करना जरूरी है। जब तक पिछड़े और वंचित समाज की जातियों का सही आंकड़ा नहीं उपलब्ध हो पाएगा तब तक उन्हें हक और सम्मान नहीं दिलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी शामिल किया था।

उन्होंने कहा कि पिछड़े, वंचित समाज का तब तक भला कैसे हो सकता है जबतक उनकी संख्या का पता न हो। उन्होंने कहा कि गिनती न होने पर तमाम जातियां इस देश में अपने अधिकार व सम्मान और शिक्षा से बहुत पीछे छूट गई है जैसे- बिंद, माली, काछी, कश्यप, पाल, धनगर, गडरिया, कुमार, लोहार बढ़ाई, निषाद, माली, लोधी, कुशवाहा, राठौर, नाई, चौरसिया आदि। ऐसी ही और भी तमाम जातियां हैं जोकि अपने अधिकारों से वंचित हैं।

उन्होंने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश भर में जागरूकता

अभियान के रूप में जातीय जनगणना पर संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछड़ों दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर उनके हक छीनने का काम शुरू कर दिया है। ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉ राम मनोहर लोहिया व दिवंगत मुलायम सिंह जी के संघर्षों से मिले अधिकारों को छीनने का काम कर रही है।

डा कश्यप ने समाजवादी साथियों का आह्वान कि वे जातीय जनगणना के लिए जागरुकता अभियान चलाकर सरकार पर दबाव बनाएं ताकि गणना के बाद पिछड़ों व दलितों को उनका हक व सम्मान दिलाया जा सके।

संगोष्ठी को सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल, पूर्व सांसद ऊषा वर्मा, पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी, पूर्व अध्यक्ष शराफत अली, पूर्व अध्यक्ष पदमराग सिंह यादव पम्मू, पूर्व विधायक आसिफ खान बब्बू, जिला महासचिव वीरेंद्र सिंह यादव वीरे, पूर्व प्रत्याशी ब्रजेश वर्मा टिल्लू, रईस अंसारी चेयरमैन संडीला, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा मुजीब खान, अजयपाल सिंह, इलाहबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष उदय यादव, जुगुल वाल्मीकि आदि ने संबोधित करते हुए जातीय जनगणना की जोरदार वकालत की।

आम बजट
गरीब-ग्रामीण पर चोट

प्रेम कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

देश में आम चुनाव से पूर्व पूर्ण आम बजट में ग्रामीण और गरीब डंके की चोट पर उपेक्षित कर दिए गये हैं। खाद, खाद्य, पेट्रोलियम व अन्य सब्सिडी कम कर दी गयी हैं। वहीं जिन तीन मंत्रालयों के बजट में कटौती की गयी है वे भी इसी ग्रामीण और गरीब वर्ग से संबंधित हैं। ये मंत्रालय हैं खाद्य एवं जनवितरण, रसायन एवं खाद और ग्रामीण विकास मंत्रालय। बोलचाल की भाषा में इसे गरीबों की साइकिल पंचर कर देना कहते हैं। क्या ग्रामीणों और गरीबों को

यूं घटा मनरेगा का बजट

वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रुपये)	पुनरीक्षित बजट आवंटन (करोड़ रुपये)
2023-2024	60,000	
2022-2023	73,000	89,400
2021-2022	73,000	98,468
2020-2021	61,500	1,11,500

कोविड काल यानी 2020-21 में मनरेगा पर खर्च आवंटित बजट से 81 प्रतिशत ज्यादा हुआ। मनरेगा पर खर्च की राशि 1,11,500 करोड़ तक जा पहुंची। मगर, 2023-24 में मनरेगा का बजट कोविड काल के स्तर से नीचे हो गया है। 2023-24 में 60 हजार करोड़ रुपये ही मनरेगा के लिए आवंटित किए गये हैं। इससे केंद्र सरकार की मंशा सवालों के घेरे में आ गयी है।

मनरेगा ऐसी योजना है जिसने गरीबों के लिए 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया है और इस योजना से जुड़ने वाली तादाद कोविड काल को छोड़ दें तो लगातार बढ़ती रही है। मनरेगा में काम मांगने वाले 2020-21 में 8.55 करोड़ लोग थे जो 2021-22 में 8.05 करोड़ रह गये। 2019-20 में 6.16 करोड़ लोगों ने मनरेगा के तहत काम मांगे। मगर, 2022-23 में 24 जनवरी 2023 तक यह संख्या 6.4 करोड़ पहुंच चुकी है।

सवाल यह है कि मनरेगा का बजट कम करके करोड़ों लोगों की पेट पर लात मारने का काम क्यों किया जा रहा है? 2008 से 2014 तक यूपीए सरकार में मनरेगा पर 1.91 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए थे। 2014 से 2023 (24 जनवरी तक) के बीच करीब 6 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गये। ग्रामीण लोगों और खासकर गरीब लोगों को रोजगार देने में यह योजना सफल रही है। ऐसे में मनरेगा का बजट कम करना चौंकाने वाली बात है! अर्थशास्त्रीय नजर से भी देखा जाए तो इससे मुद्रा के सर्कुलेशन पर असर पड़ेगा और गरीब लोग बढ़ती महंगाई का सामना

इन तीन मंत्रालयों में बजट घटने से बढ़ेगी गरीबों की परेशानियां

मंत्रालय	बजट 2021-2022	बजट 2022-23	पुनरीक्षित 2022-23	बजट 2023-24	प्रतिशत बदलाव (पुनरीक्षित बजट 2022-23 के मुकाबले 2023-24 का बजट)
खाद्य एवं जनवितरण	3,05,571	2,17,684	2,96,523	2,05,765	-30.6%
रसायन और खाद	1,54,789	1,07,715	2,27,681	1,78,482	-21.6%
ग्रामीण विकास	1,61,791	1,38,204	1,82,913	1,25,036	-12.3%

बजट में किसानों-बेरोजगारों की फिक्र नहीं

केंद्र सरकार के आम बजट में किसानों, बेरोजगारों के लिए कोई योजना न होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आम बजट में किसानों के लिए सरकार ने नई मंडी और एमएसपी के बारे में कोई प्रावधान नहीं किए हैं। युवाओं को उम्मीद थी कि इस बजट में रोजगार पर बात होगी लेकिन उन्हें निराशा मिली है। श्री यादव ने मंहगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बुनियादी मुद्दों पर भाजपा सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने यह नहीं बताया है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कहां से देंगे? स्मार्ट सिटी का भी कोई जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेस-वे व नए पाॅवर प्लांट लगाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कोई नई

मंडी बनाने, एमएसपी आदि के लिए घोषणा न करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जीएसटी पर कोई चर्चा न करना भी सवाल खड़ा करता है क्योंकि व्यापारी वर्ग इससे सर्वाधिक परेशान है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि 10 साल की सरकार के अंतिम बजट में गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने किसान की आय दुगनी करने और 2 करोड़ नौकरियां देने की झूठी दिलासा दिलाई थी। पिछले बजट में कृषि मंडियों के लिए एक लाख करोड़ रुपये रखे गए थे लेकिन एक भी नई मंडी नहीं बन सकी।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार देश को आत्मनिर्भर नहीं, आयात निर्भर बना रही है। देश पर कर्ज बढ़ रहा है। गलत आर्थिक नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री, महंगाई कम करने के वायदे के साथ सत्ता में आए थे लेकिन अब वह यह बात भूल गए हैं। बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। श्री यादव ने कहा कि देश को बुलंदियों पर ले जाने का दावा और कुछ नहीं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। भाजपा की नीतियों से देश आर्थिक, राजनैतिक रूप से सालों पीछे चला गया हैं । जनता अब भाजपा के भ्रमजाल में फंसने वाली नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भाजपा को हराएगी।

करने में असमर्थ होंगे।

खाद्य एवं जनवितरण मंत्रालय का बजट 30 फीसदी से भी ज्यादा कम हुआ है। कहने की जरूरत नहीं कि यह विभाग अत्यंत गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्रिय रहता है। 2022-23 के पुनरीक्षित बजट के मुकाबले 2023-24 के बजट में सबसे ज्यादा 30.6 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गयी है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि केंद्र सरकार ने पांच किलो अनाज मुफ्त में बांटने की योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

रसायन और खाद मंत्रालय के बजट में 2022 के मुकाबले 2023 में 21.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी है। खेती-किसानी पर इसका सीधा और गंभीर असर पड़ेगा। महंगे खाद ने किसानों की कमर पहले से तोड़ रखी है। ऐसे में सरकारी मदद की उम्मीद भी अब खत्म होती दिख रही है। जब बजट ही कम होगा तो सब्सिडी की बात भी किसान नहीं सोच सकते।

ग्रामीण विकास के लिए बजट में 12.3 प्रतिशत की गिरावट आयी है। 2021-22 में 1.61 लाख करोड़ का बजट 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ का होकर रह गया है। पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी ग्रामीणों की कीमत पर ही की गयी है। पूंजीगत व्यय का बजट 10 लाख करोड़ पार कर गया है। मतलब साफ है कि ग्रामीण मुश्किल झेलकर देश की आधारभूत संरचना का निर्माण करेंगे।

सब्सिडी कम कर या घटाकर अगर गरीबों का कल्याण होता है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार ऐसा करने में जुटी दिखती है। 2021-22 में कुल सब्सिडी 5लाख करोड़ रुपये से ज्यादा थी जो 2022-23 में घटकर

3.55 लाख करोड़ रह गयी। हालांकि पुनरीक्षित बजट अनुमान 5.62 लाख करोड़ रुपये रहा। 2023-24 में घटकर यह 4 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा रह गया।

सब्सिडी घटने से किसानों पर बोझ बढ़ेगा। लाभकारी नहीं रह गयी खेती की स्थिति और खराब होगी। किसान बदहाल होंगे। कुपोषण से जूझते हिन्दुस्तान में खाद्य सब्सिडी घटना वाकई चिंताजनक बात है। खाद्य सब्सिडी में सबसे ज्यादा 31.3 फीसदी की गिरावट और भी चिंता की बात है। खाद सब्सिडी में 22.3 फीसदी की गिरावट ने किसानों के कान खड़े कर दिए हैं। इससे खाद महंगे होंगे और खेती भी। जाहिर है अलाभकारी खेती से दूर भागेंगे किसान।

पेट्रोलियम सब्सिडी में 75 फीसदी से ज्यादा की गिरावट ने हर किसी को हैरान कर दिया है। महंगाई रोकने की चिंता से दूर यह कदम महंगाई बढ़ाने वाली है। तमाम तरह की सब्सिडी को मिलाकर देखें तो 28.3 फीसदी की गिरावट वास्तव में ग्रामीण और गरीब लोगों की कमर तोड़कर रख देगा। केंद्र सरकार ने खाद्य, खाद और पेट्रोलियम पर खर्च को 2023-24 में 3.74 लाख करोड़ रहने का अनुमान जताया है। यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत कम है।

आम बजट में एक और बात महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे को 3.5 फीसदी तक सीमित रखने का निर्देश दिया है। जबकि, खुद केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा इस वक्त 6.4 फीसदी है और इसे 2023-24 में घटाकर 5.9

सब्सिडी में कमी

विभिन्न मदों में सब्सिडी	वास्तविक बजट 2021-22	बजट 2022-23	पुनरीक्षित 2022-23	बजट 2023-24	प्रतिशत बदलाव (2022-23 में वास्तविक बजट के मुकाबले 2023-24 का बजट)
खाद्य सब्सिडी	2,88,969	2,06,831	2,87,194	1,97,350	-31.3%
खाद सब्सिडी	1,53,758	1,05,22	2,25,220	1,75,100	-22.3%
पेट्रोलियम सब्सिडी	3,423	5,813	9,171	2,257	-75.4%
अन्य सब्सिडी	57,758	37,773	40,495	28,377	-29.9%
कुल	5,03,907	3,55,639	5,62,080	4,03,084	-28.3%

फीसदी के स्तर पर ले जाना है। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारों पर कम व्यय का दबाव डालकर केंद्र सरकार अपने लिए व्यय की संभावनाएं पैदा कर रही हैं? यह कदम निश्चित रूप से देश के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा।

2021-22 में राज्यों के लिए कुल 4,60,575 करोड़ रुपयों का हस्तांतरण केंद्र सरकार की ओर से किया गया था। वर्ष 2022-23 के बजट में इसे घटाकर घटाकर 3,67,204 करोड़ रुपये कर दिया और संशोधित अनुमानों के अनुसार बाद में इसे और भी घटाकर, 3,07,204 करोड़ पर ले आया गया है। ताजा आम बजट में राज्यों को हस्तांतरण के लिए सिर्फ 3,59,470 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साफ है कि जीएसटी के दौर में कर राजस्व के लिए केंद्र पर पहले से ज्यादा निर्भर हुई राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ने वाली है।

आम बजट को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने पर यह नज़र आता है कि पूंजीगत व्यय को 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का कदम राज्यों से कुर्बानी मांग रहा है। 10 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 3 प्रतिशत है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य विभिन्न प्रदेशों और देशभर की गरीब ग्रामीण जनता से भी कुर्बानी की अपेक्षा कर रहा है।

केंद्र सरकार का राजस्व घाटा 2021-22 में जीडीपी का 4.4 फीसदी था जो 2022-23 में 4.1 फीसदी पर पहुंच गया। 2023-24 में राजस्व घाटे को 2.9 फीसदी के स्तर पर पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन, जिस तरीके से केंद्र पर उधार चढ़ रहे हैं वह चिंताजनक है।

गरीबों और ग्रामीणों पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन कॉरपोरेट जगत पर मेहरबानी की जा रही है। कॉरपोरेट टैक्स से वसूल की जाने वाली राशि आम लोगों से वसूली जानी वाले राशि के मुकाबले कम है। मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव कर अवश्य लुभाने की कोशिश की गयी है। लेकिन, इससे यह भी साबित हुआ है कि मोदी सरकार ने टैक्स की जो नयी प्रणाली विकसित की थी उसके अच्छे नतीजे नहीं मिले।

फोटो स्रोत : गूगल

ऑस्ट्रेलिया ने जाना समाजवादी सिद्धांतों का मर्म

बुलेटिन ब्यूरो

आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त वैरी ओ फैरल एओ व दूतावास के अन्य राजनयिकों ने 11 फरवरी को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचकर यूपी में पिछली समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को जाना-समझा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों को जानने में भी रुचि दिखाई। उन्हें बताया गया कि समाजवादी पार्टी के पास विकास का विजन है और यूपी में वही भाजपा का सशक्त विकल्प है।

आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर जाने की इच्छा जताई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उन्हें आमंत्रित किया और

पार्टी नेताओं से उनका भव्य स्वागत करने की हिदायत दी। आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त वैरी ओ फैरल एओ तथा दूतावास के अन्य अधिकारियों का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी एवं सर्वश्री आलोक रंजन, उदयवीर सिंह, प्रो सुधीर पंवार ने स्वागत करते हुए प्रदेश की राजनीतिक स्थिति एवं समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की।

राजनयिकों ने समाजवाद व समाजवादी पार्टी की नीतियां जाननी चाहीं तो उन्हें बताया गया कि समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता डॉ राम मनोहर लोहिया की नीतियों से समाजवादी पार्टी प्रभावित है। उनकी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती के लिए संघर्षशील रही है। विदेशी मेहमानों को बताया गया कि श्री अखिलेश यादव का नेतृत्व सर्वसमाज में स्वीकार्य है। उत्तर प्रदेश में उनके कुशल नेतृत्व में वर्ष 2012 से 2017 तक जो विकास कार्य हुए उनकी प्रशंसा देश में ही नहीं विदेशों तक में हुई है।

समाजवादियों ने राजनयिकों को बताया कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। यहां सक्षम सरकार की आवश्यकता है। समाजवादी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया था। यूपी के राजनीतिक हालात के बारे में राजनयिकों की रुचि देखते हुए उन्हें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भाजपा का सशक्त विकल्प है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए ठोस विकास कार्य किए हैं जिसकी अवाम कायल है।

मेहमानों को बताया गया कि विकास और कानून व्यवस्था में सीधा सम्बंध है। उत्तर प्रदेश में जो भी विकास दिखता है वह समाजवादी सरकार की ही देन है। आईटी हब, मेट्रो रेल, गोमती रिवरफ्रंट, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे आदि विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल में हुए।

संत रविदास ने सर्वसमाज को दिशा दी

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी ने महान संत रविदास की जयंती सादगी के साथ मनाते हुए उन्हें नमन किया। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संत रविदास ने सर्वसमाज को दिशा दी। वह महान संत व समाज सुधारक थे।

5 फरवरी को संत रविदास जयंती पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय समेत सभी जिलों के पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

संत रविदास की जयंती पर श्रद्धा व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया था। वह संत के साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने देश को एक ईश्वर का उपदेश दिया था। वह ऊंच नीच व जात पात के विरोधी थे। वह महान संत थे। कबीरदास ने उन्हें अपने से वरिष्ठ तथा महान संत की संज्ञा दी थी। शश्री यादव ने कहा कि संत रविदास ने सर्वसमाज को दिशा दी थी।

बेनी बाबू का यूपी के विकास में बड़ा योगदान

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की 82वीं जयंती 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में सादगी से मनाई गई। स्वर्गीय बेनी वर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए समाजवादी पार्टी ने यूपी के विकास में उनके योगदान पर चर्चा की। पिछड़ों की लड़ाई का योद्धा बताते हुए समाजवादियों ने कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।

प्रदेश के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ही उनके कृतित्व पर समाजवादियों ने प्रकाश डाला और उनके बताए रास्ते पर चलकर सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के चित्र पर राष्ट्रीय सचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री बेनी बाबू को याद करते हुए श्री अखिलेश यादव ने हमेशा कहा है कि बेनी बाबू जी समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे। वे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के निकट सहयोगी थे। किसानों एवं आमजन की समस्याओं को सड़क से सदन तक उठाते रहे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका बहुत योगदान रहा है।

साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 08 Feb

नक़ली संवेदना का नक़ली चेक।

दलित बच्चे की पिटाई से हुई मौत के बदले मुआवज़े का चेक जब बैंक में ख़ारिज हो गया तो अब भाजपा का शासन-प्रशासन मुँह छिपाने के लिए कह रहा है वो चेक प्रतीकात्मक था।इससे बचकानी बात और क्या होगी।

भाजपा में सब कुछ प्रतीकात्मक है, अच्छा हो कहा जाए छलात्मक है।

दलित बच्चे की मौत पर परिवार को मिला कैंसिल चेक: औरैया DM बोले- चेक प्रतीकात्मक था, टीचर की पिटाई से हुई थी बच्चे की मौत

राजेश साहू 1 मिनट पहले

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · 3d

भाजपाई G-20 में रंगारंग कार्यक्रम का साक्षात् आंनद उठा रहे हैं लेकिन बगल में कानपुर के पीड़ितों से दूर से ही मोबाइल पर बात कर रहे हैं।

कानपुर के अग्निकांड में क्या भाजपाइयों की आँख का पानी भी जलकर भस्म हो गया है।

निंदनीय, शर्मनाक!

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 07 Feb

बस का किराया 24% बढ़ाकर क्या उप्र की भाजपा सरकार इंवेस्टमेंट समिट का खर्चा जनता की जेब से निकालना चाहती है क्योंकि उन्हें मालूम है, न अब तक पिछला निवेश आया है और न अगला आएगा।
अमीरों की पोषक भाजपा ने महंगाई को ग़रीब व आम जनता की नियति बना दिया है।
भाजपा के हटने से ही महंगाई हटेगी।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

दिखावटी भाजपाई संवेदना का शर्मनाक वीडियो!

भाजपाइयों ने अपना हिस्सा तो दिखा दिया लेकिन पीड़ित की माँग का हिस्सा काट दिया। ये भाजपाई असंवेदनशीलता का निकृष्टतम रूप है।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

शासन-प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाएं तो समझ लेना चाहिए उनका अंत निकट है।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

काशी के घाटों पर गंदगी से मुक्ति की इच्छा लिए माँ गंगा अब किसे पुकारे, किस बुलाये।

Translate Tweet

2 दैनिक जागरण ... 7 फरवरी, 2023 वाराणसी

सिसक रही गंगा...

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

अंतिम संस्कार का अंतिम अधिकार भी छीन लेना भाजपा सरकार की रीति बन गयी है... चाहे हाथरस हो या कानपुर।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाज के वंचित एवं शोषित वर्ग के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन।

Translate Tweet

Following

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 06 Feb

माननीय से निवेदन है कि थोड़ा 'इनवेस्टमेंट' सुरक्षा पर भी करें। मुख्यमंत्री जी के आवास से फूलों के गमले चोरी होने की ख़बर उच्च सुरक्षा क्षेत्र के लिए शोभनीय नहीं।

माननीय से आग्रह है विविध रंगों के फूलों को भी बचाइए और विविधता की सुगंध को भी।

लखनऊ: इन्वेस्टर्स समिट से पहले सीएम आवास से फूल के 100 गमलों की हुई चोरी

06:27:48 pm - Feb 05, 2023

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · 3d

ज़ीरो तो भारत की ही देन है, मुख्यमंत्री जी निवेश के नाम पर जितने चाहे उतने लगा लें। खरबों के निवेश की बात तो वो कई बार कर चुके हैं पर ज़मीन पर कब उतारेंगे? अगर ये सच है तो खाद की बोरी में 5 किलो वापस बढ़ा दें और साथ ही खाद व गैस पर सब्सिडी भी दे दें। जनता को भी तो कुछ लाभ हो।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं कृपया इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति-वर्ण को लेकर क्या वस्तुस्थिति है।

Translate Tweet

'भगवान के सामने कोई जाति-वर्ण नहीं, श्रेणी पंडितों ने बनाई,' कास्ट सिस्टम पर बोले भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं. उनमें कोई जाति, वर्ण नहीं है., लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था. भारत देश हमारे हिन्दू धर्म के अनुसार चलकर बड़ा बने और वो दुनिया का कल्याण करे. उन्होंने आगे कहा कि हिन्दू और मुसलमान सभी एक ही हैं

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

स्व. कैलाश यादव जी की प्रतिमा का अनावरण एवं जनसभा, गाज़ीपुर।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Warm birthday wishes to Shri K. Chandrashekhar Rao ji. Wishing you good health and a great year ahead.

@TelanganaCMO

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · 3d

अकबरपुर रनिया विधानसभा से तीन बार सपा विधायक रहे श्री रामस्वरूप सिंह गौड़ जी का निधन, अत्यंत दुःखद है।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।

ॐ शांति!

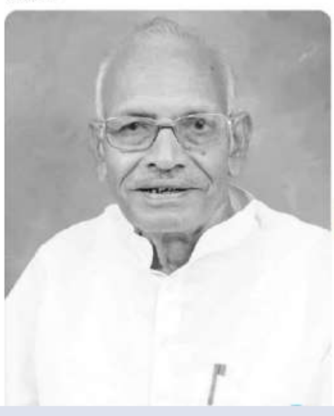

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भारत के महान शूरवीर योद्धा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

मीडियाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार सत्ताधारियों की हताशा का प्रतीक है। जब सत्ता पत्रकारों पर प्रहार करने लगे तो समझ लो वो सच से डर गयी है।

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 07 Feb

इलाहाबाद की वरिष्ठ सपा नेता सबीहा मोहानी जी की मृत्यु अत्यंत दुःखद है।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति व समस्त शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

बुलडोज़र

जो देते हैं घरों को तोड़ने का आदेश
बुलडोज़र सबसे पहले
उनकी आत्मा पर चल चुका होता है
उसके बाद ही वह दस-बीस घरों के साथ
दस-बीस लाख बेबस लोगों के सीने को रौंदता है

तालियाँ बजाने वाले दस-बीस करोड़ लोगों के विवेक
कब रौंद डाले जाते हैं
यह तो बुलडोज़र को भी पता नहीं होता

उसके बड़े-बड़े जबड़ों में मिट्टी और चट्टानें ही नहीं आहें
और चीत्कारें भी फँस रही होती हैं
बच्चों के रुदन और स्त्रियों के आँसुओं से
गीली हुई मिट्टी चिपक रही होती है
उसके विशाल चक्कों से

नए लोकतन्त्र के इस नए गारबेज के बारे में
कुछ पता नहीं होता
बुलडोज़र बनाने और चलानेवालों को

आइंस्टीन को भी कहाँ पता था
कि दुनिया को ऊर्जा समृद्ध करने के लिए
खोजा था जिस परमाणु विखण्डन की प्रक्रिया को उसका
इस्तेमाल मनुष्यता के विनाश के लिए
किया जाएगा !

- मदन कश्यप-

(साभार: कविता कोश)

समाजवादी पार्टी

/samajwadiparty

www.samajwadiparty.in